

न्याय की जा रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को खेतों के साथ-साथ सोलर पावर उत्पादन, हनी प्रोसेसिंग और जूट उद्योग जैसे नए क्षेत्रों से नए नौकरों का निर्देश दिया।

चायतों में पारदर्शिता व डिजिटल सेवाओं पर जोर: पंचायती राज विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह, महिला हिंसा और हेल्पलाइन नंबरों को लेकर जागरूकता अभियान लाने को कहा। पंचायत भवनों में ठोस कचरा प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने, गीले और सूखे कचरे को अलग करने तथा प्लास्टिक व्यवस्थापन पर भी बल दिया। सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवालयों में लोगों को समय पर सभी सेवाएं मिलनी चाहिए। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं के विस्तार, शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और लाइट जैसी निम्नतम सुविधाओं को प्रभावी तरीके से लागू करें।

सरोप: OSM का काम ब्लैक लिस्टेड...

सीएम ने कहा, 'कॉपी की डिजिटल जांच के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल अप्रैल 2025 को सेंट्रल पब्लिक प्रॉक्योरमेंट पोर्टल पर जारी कर योग्य को ठेका दिया गया।' हालांकि सीबीएसई के सूत्रों ने बताया कि ठेका एस्टिमेट को ही दिया गया है। कंपनी चुने जाने को लेकर लगाए गए सरोप निराधार है।

गैमिंग वाले ऑनलाइन गेम पर बैन सही...

सीएम, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे गेम भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट किया है कि कोई गेम स्किल पर हो या चान्स पर, अगर उसमें पैसा शामिल है तो राज्य सरकारें उसे रेगुलेट कर सकती हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट: तमिलनाडु 2020 में ऑनलाइन दांव वाले गेम्स पर रोक के लिए ऑर्डिनंस लाया, जिसे 2021 में कानून बनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने अप्रैल 2021 में इसे रद्द कर दिया। कर्नाटक सरकार ने भी 2021 में ऑनलाइन दांव, टोकन, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग पर कानूनी दायरे में लाया लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में इसे रद्द कर दिया। इसके बाद दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

रुल के पूर्व सीएम विजयन के घर ईडी...

मार्च 2019 में आयकर विभाग ने सीएमआरएल पर छापा मारा। इसी दौरान करीब फर्जी खर्चों का पता चला था। सीएमआरएल ने एक मकमल टैक्स सेटलमेंट कमीशन के सामने भी फर्जी खर्चों की स्वीकार की थी। सीएमआरएल के एमडी शशिधरन एक अन्य एम्प्लॉयर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रालि भी चलाते हैं। इस कंपनी ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये का कर्ज दिया था। लेकिन एक्सालॉजिक वह भी नहीं चुका पाई। ईडी का दावा है कि सीएमआरएल की वीणा ने अपराध से संपत्ति अर्जित की। आयकर विभाग के एस प्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के मुताबिक, सीएमआरएल ने वर्षों में 182 करोड़ रुपये के काल्पनिक नकद खर्च दिखाया। आयकर विभाग द्वारा एक्सालॉजिक को बिना किसी सेवा पेमेंट किए जाने रोपों ने केरल में जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। लगातार विजयन पर निशाना साध रहा था और उनके परिवार पर भी निशाना साधने का आरोप लगा रहा था। यह विजयन सरकार के सामने आए सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवादों में से एक रहा है।

सरकार इनसाइट विजयन के पावर सेंटर से राजगी, विकास मॉडल की जांच हो सकती है

छापे ने केरल की राजनीति के अंदरखाने चल रहा संघर्ष उजागर किया है। पार्टी के भीतर उत्तराधिकार और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हैं। पार्टी नेताओं में नाराजगी है कि पूरी सत्ता विजयन तक गई है। सरकार के कुछ हिस्सों तथा कॉर्पोरेट हितों के बीच बढ़ती तनाव भी चुभने लगी है। इस विवाद ने विजयन के कार्यकाल के केरल के विकास मॉडल की जांच को फिर से तेज कर दिया है, एंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, खनन और तटीय परियोजनाओं में बड़ी परियोजनाओं की बढ़ती भूमिका को लेकर जांच का दायरा बढ़ सकता है।

बिक्री की घोषणा

वसूली अधिकारी का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, झारखण्ड

वसूली प्रक्रिया सं. 304/2024

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लिए बकाये ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की घोषणा

पंजाब नेशनल बैंक, प्रथम तल, फिरोजाला बिल्डिंग, रांची बनाम मेसर्स द ARC फर्नीचर एवं अन्य

सेवा में,

- (1) मेसर्स द ARC फर्नीचर, प्रोपराइटर श्रीमती चंचल देवी, पति श्री राम कुमार, R/o - बिजुलिया तालाब रोड, दीनबन्धु नगर, रानी सती मंदिर के निकट, रामगढ़ कैट, रामगढ़ - 829122
- (2) श्रीमती चंचल देवी, प्रोपराइटर मेसर्स द ARC फर्नीचर, पति श्री राम कुमार, R/o - पलैटन नं. 101, ब्लॉक नं. 21, सेक्टर - 1, खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, होटवार, रांची - 834009
- (3) श्री गिरीश कुमार, पिता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह, R/o - बिजुलिया तालाब रोड, दीनबन्धु नगर, रानी सती मंदिर के निकट, रामगढ़ - 829122

1. जबकि आप प्रमाणपत्र के अनुसार भुगतान करने योग्य ब्याज एवं लागत सहित पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची द्वारा जारी किये 2021 का ओ.ए. वाद सं. 198 में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके द्वारा भुगतान रु. 41,53,788.00/- (रुपये इकतालीस लाख तिरपन हजार सात सौ अठ्ठासी मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

2. और जबकि अदोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि में नीचे के अनुसूची में उल्लेखित संग्रह संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. और जबकि 29.04.2026 को प्रमाण पत्र के अनुसार रु. 44,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) की लागत के अलावा पूरा एवं अंतिम वसूली तक रॉकटलाइट और 01.08.2021 से 12.10% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित रु. 41,53,788.00/- (रुपये इकतालीस लाख तिरपन हजार सात सौ अठ्ठासी मात्र) की राशि बकाया होगा।

4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, स्थान के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में, उक्त संपत्ति को 08.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ बेचा जाएगा। <https://www.baanknet.com> (PSB Alliance Private Limited) के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' से ई-नीलामी और बोली द्वारा बेचा जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें: वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची. संपर्क सं. 065-224021 एवं सम्पत्ति निरीक्षण के लिये श्री संजीव कुमार, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, ARMB शाखा, रांची, मोबाइल सं. 7300705205 से संपर्क करें।

4.1 नीचे वर्णित अनुसूची में उपरोक्त नाम वाले प्रमाणपत्र देनदार की संपत्ति बेची जायेगी और उक्त संपत्ति से जुड़े हुए दायित्व और दावे जो कि सुनिश्चित किये गये हैं उनका विवरण अनुसूची में प्रत्येक लॉट के समक्ष वर्णित है।

4.2 अनुसूची में वर्णित लॉट के अनुसार संपत्ति की बिक्री की जायेगी। यदि संपत्ति की एक अंश की बिक्री से होने वाली वसूली राशि से संतुष्टि होती है बाकी संपत्ति की बिक्री तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रुक जायेगी यदि किसी लॉट में नीलामी बोली खल होने के संकेत होंगे, उक्त में वर्णित बकाया, ब्याज, लागत (बिक्री की लागत समेत) बिक्री संचालित करने वाले पदाधिकारी के समक्ष जमा कर दिये जायें या उनकी संतुष्टि के लिए वह प्रमाणित कर दिया जाये कि उस सर्टिफिकेट की राशि, ब्याज और लागत का भुगतान अदोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

4.3 बेची जाने वाली संपत्ति पर अन्य व्यक्ति के किसी भी अधिकारी या जो बिक्री प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाने, अधिग्रहण का प्रयास करने का ज्ञातेकर नहीं है। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 96 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों के तहत और इसके बाद के नियमों के अधीन होगी।

4.4 अदोहस्ताक्षरी के श्रेष्ठ सूचना के अनुसार उल्लेखित अनुसूची में विवरणों को शामिल किया गया है लेकिन किसी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण या इस घोषणा में किसी तथ्य के चूक के लिए अदोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होगा।

5. (ए) विवरण के अनुसार आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी।

संपत्ति का विवरण		अनुसूची 'A'	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी
बैंक रकम ईडी भूमि के सभी भाग, जो प्लॉट सं. 940, खाता सं. 94, वार्ड सं. 8, क्षेत्रफल - 3 हिसमिल, ग्राम - रामगढ़ कैट, थाना सं. 82, अंचल - रामगढ़ कैट, जिला - रामगढ़ में स्थित है तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं - उत्तर : अकलू महतो एवं अन्य, दक्षिण : सड़क, पूर्व : रविन्द्र कुमार रवि, पश्चिम : अरुण कुमार। उक्त बैंक संपत्ति श्री गिरीश कुमार, प्रमाण-पत्र देनदार संख्या - 3 के नाम पर बिक्री विधेय संख्या 1605 दिनांक 22.04.2009 के माध्यम से दर्ज है।		रु. 29,32,500/-	रु. 29,32,500/-	रु. 2,93,250/-

6. इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी जमा करने की आवश्यकता होगी साथ में पैन कार्ड, पहचान पत्र, पता के लिए प्रमाणपत्र इत्यादि जमा करना होगा और कंपनी होने पर, बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि या कंपनी के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाला कोई भी अन्य दस्तावेज/ कंपनी का अर्द्धांश भी जमा करना होगा, इसे वसूली अधिकारी के कार्यालय में अद्यतन 06.07.2026 को 04:00 बजे तक या इससे पहले तक जमा करना है और उसके बाद वे 08.07.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। यदि नीलामी के अंतिम समय में अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

7. इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी राशि वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के खाते में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFSC कोड : SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची जमा करनी होगी।

8. बोली प्रपत्र के साथ ईएमडी को रसीद वसूली अधिकारी के कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पांचवी मंजिल, आर.आर.डी.ए. बिल्डिंग, कचहरी चौक, रांची में जमा की जाएगी।

9. वह राशि जो बोली लगाने के लिए बढ़ाई जाएगी अनुसूची 'A' के लिए रुपये 1,00,000/- होगी। बोली की राशि या बोलीदाता के रूप में उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद की स्थिति में लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा।

10. असफल बोलीकर्ता ई-नीलामी की प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद ईएमडी राशि कार्यालय, वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

11. सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को ईएमडी को समायोजित करने के बाद बोली/ बिक्री राशि के 25% 'वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची', के पक्ष में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFSC कोड : SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची में भेज दिया जाएगा। इसे अगले बैंक कार्य दिवस यानि शाम 04:00 बजे तक इस ट्रिब्यूनल के पास जमा करना होगा। इसमें विफल रहने पर ईएमडी जमा कर लिया जाएगा।

12. सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री राशि का शेष 75% वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/चे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। इसे संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले 'वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची', के पक्ष में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFSC कोड : SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची में भेज दिया जाएगा। यदि 15वें दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन होता है तो इस दिन को छोड़कर 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस में रु. 1,000/- तक 2% की दर से और रु. 1,000/- के ऊपर कुल राशि 1% की दर से पाउंडेज रजिस्ट्रार, डीआरटी, रांची के पक्ष में जमा करना है। (अगर डाक के माध्यम से शेष 75% राशि जमा करने के मामले में, उपरोक्त के अनुसार वसूली अधिकारी तक पहुंच जाना चाहिए।)

13. निश्चित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने के स्थिति में, बिक्री की नवी घोषणा जारी होने के उपरान्त, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। बिक्री का खर्च निकालने के बाद, यदि अदोहस्ताक्षरी के द्वारा जमा कर संरक्षक के पास जमा कर सकते हैं तो चूक करने वाले क्रेता को उस राशि के किसी भी हिस्से के लिए सभी दावे खारिज हो जायेंगे जिसके की इसको बाद में बेचा जाएगा।

14. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली लगाई गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। इस उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करने का निर्णय अदोहस्ताक्षरी का होगा, जबकि पेश की गई कीमत इतनी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि ऐसा करने के लिए उसे अनुपयुक्त बना दिया जाए।

15. संपत्ति जैसी है और जहाँ है/ जो है/ बिना शिकायत के आधार पर बेची गई है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है/ आगाह किया जाता है कि वे SRO के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों को सत्यापित करें और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति, विवरण, स्थिति, अदिभार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। सरकार/ स्थानीय निकाय को देय सांविधिक देय/दायित्व आदि, यदि कोई हो, जो बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए हैं, क्रेता(ओं) द्वारा वहन किए जाएंगे।

16. क्रेता की सुपरी: नीलामी क्रेता द्वारा सभी खर्चों और प्रारंभिक शुल्कों को वहन किया जाएगा। निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए हैं, क्रेता(ओं) द्वारा वहन किए जाएंगे।

17. अदोहस्ताक्षरी क्रेता द्वारा स्वामित्व विलेख प्राप्त करने और संपत्ति का कब्जा देने का मेमो दाखिल करने पर ही विचार किया जाएगा।

18. अदोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी बोली को यदि अनुचित पाया गया तो स्वीकार/अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण के मुहर से रांची में 29 अप्रैल, 2026 को जारी।

वसूली अधिकारी-1

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

SALE PROCLAMATION

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JHARKHAND AT RANCHI
IN CASE NO. 304 OF 2021
RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT 1993

Punjab National Bank, 1st Floor, Khyabala Building, Ranchi Vs. M/s The ARC Furniture & Others
(1) M/s The ARC Furniture, Proprietor Mrs. Chanchal Devi, W/o Ram Kumar, At Bhojpur Road, Dinbandhu Nagar, Near Rani Sati Mandir, Ramgarh Cantt, Ramgarh, Jharkhand - 833102
(2) Mrs. Chanchal Devi, Proprietor M/s The ARC Furniture, W/o Ram Kumar, At Bhojpur Road, Dinbandhu Nagar, Near Rani Sati Mandir, Ramgarh Cantt, Ramgarh, Jharkhand - 833102
(3) Sri Girish Kumar, S/o Anirudh Kumar, W/o Ram Kumar, At Bhojpur Road, Dinbandhu Nagar, Near Rani Sati Mandir, Ramgarh Cantt, Ramgarh, Jharkhand - 833102

- (1) Whereas you have failed to pay the sum of Rs. 41,53,788.00 (Rupees Forty One Lakh Fifty Three Thousand Seven Hundred Eighty Eight Only) payable by you in respect of Recovery Order No. 304 of 2021 issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi along with the interest and costs as per the certificate.
- (2) And whereas the undersigned has ordered the attached property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said sum of Rs. 41,53,788.00 (Rupees Forty One Lakh Fifty Three Thousand Seven Hundred Eighty Eight Only) under a sum of Rs. 41,53,788.00 (Rupees Forty One Lakh Fifty Three Thousand Seven Hundred Eighty Eight Only) and future interest @ 12.10% compound interest monthly from the date of the said order.
- (3) And whereas as on the 29.04.2026 there was a balance of Rs. 44,000/- (Rupees Forty Four Thousand Only), as per the certificate.
- (4) Notice is hereby given that, in the absence of a sale place through "Online Electronic Bidding" on the website <https://www.baanknet.com> (PSB Alliance Private Limited) on 08.07.2026 between 11:00 AM to 12:00 Noon, the said property shall be sold by e-auction and bidding shall be open for a duration of 5 minutes duration after 12 noon if required.
- (5) The sale will be of the property of the certificate holder mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property so far as they have been specified in the schedule against each lot.
- (6) The property will be put up for the sale in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediate. If the amount to be realized is not satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediate. If the amount to be realized is not satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediate.
- (7) No officer of other person, having any duty to perform, shall attempt to acquire any interest in the property sold, subject to the conditions prescribed in the Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under.
- (8) The particulars specified in the annexed schedule shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
- (9) The reserve price below which the property shall not be sold is Rs. 29,32,500/-.

Details of Properties

All that piece and parcel of mortgaged land situated at Village:- Ramgarh Cantt, Thana No. 82, Anchal:- Ramgarh Cantt, District:- Ranchi, Jharkhand, bounded by:- North:- Aklu Mahto & Other, South:- Road, East:- Ravindra Kumar, West:- Girish Kumar, Certificate Debit No. 1605 dated 22.04.2009.

(6) The interested bidders are required to deposit EMD along with documents PAN Card, Identity Proof, Address Proof etc. and in the case of company, copy of resolution passed by the Board Members of the Company or any other documents claiming representation / attorney of the company also, latest by 08.07.2026 before 4:00 PM in the office of the Recovery Officer, DRT, Ranchi and thereafter they shall be eligible to participate in the e-auction. The closing time will automatically get extended for 5 minutes.

(7) The intending bidders shall pay the EMD amount in the account of Recovery Officer, DRT, Ranchi through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, IFS Code : SBIN0007507, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi.

(8) The receipt of EMD along with bid form shall be deposited before the Office of the Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal, 5th Floor, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi.

(9) The amount by which the bidders are to be increased shall be Rs. 1,00,000/- in Schedule 'A' in the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

(10) The unsuccessful bidder shall take EMD directly from the Office of Recovery Officer, DRT, Ranchi immediately on closure of the e-auction sale proceeds.

(11) The successful/ highest bidder shall have to pay for 25% of the bid amount after adjusting the EMD amount in the account of Recovery Officer, DRT, Ranchi through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, IFS Code : SBIN0007507, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi, by next bank working day i.e. by 04.00 PM with this Tribunal failing which the EMD shall be forfeited.

(12) The successful/highest bidder shall deposit in the account of Recovery Officer, DRT, Ranchi through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, IFS Code : SBIN0007507, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi, the balance 75% of the sale proceed before the Recovery Officer, DRT, Ranchi on or before 15th day from the date of auction of the property exclusive of such day or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day along with poundage @ 2% upto Rs. 1,00,000/- and @1% on the excess of such gross amount over Rs. 1,00,000/- in favour of Registrar, DRT, Ranchi. In case of deposit of balance amount of 75% through post, the same should reach the Recovery Officer as above.

(13) In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be re-sold, after the issue of fresh Proclamation of Sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeited all claims to the property of to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

(14) The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid by him is not less than the Reserve Price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline/ acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.

(15) The property is sold on as is and where is /on what it is/ no complaint basis. Bidders are advised/cautioned to verify with the SRO as well as the Revenue Records and shall satisfy themselves regarding the nature, description, condition, encumbrance, lien, charge, statutory dues, etc. over the property before submitting their bids. Statutory dues/ liabilities etc. due to the Government/Local Body, if any, shown in the sale notice/tender document shall be borne by the purchaser(s).

(16) Delivery of Possession :- All expenses and incidental charges thereto shall be borne by the auction purchaser. Request for appropriation of sale proceeds by the Certificate Holder Bank/Financial Institution will be considered only upon the auction purchaser filing a memo of having received the title deeds and delivered possession of the property.

(17) The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at anytime without assigning any reason.

Given under my hand and seal of this Tribunal at Ranchi on this 29th day of April, 2026

RECOVERY OFFICER II

down at be RaGa: Party

Continued From P 1

If all goes to plan, Siddaramaiah's resignation would mark the culmination of a prolonged internal tussle that Congress has consistently played down. Party insiders familiar with the developments said Siddaramaiah agreed to step down at the behest of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, whom the veteran credits with backing him to become CM twice despite the presence of stronger contenders. Siddaramaiah had been maintaining all along that he would make way for a new face if Rahul asked him to do so. The Ahinda strongman has so far held office for eight years and 12 days across two terms, surpassing his mentor and backward class champion D Devaraj Urs.

For Shivakumar, Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra's backing played the decisive behind-the-scenes role in his likely elevation to the CM's post during Wednesday's discussions in Delhi, sources said.

They said Shivakumar;

SC: Online gaming are not mere facilitators

Continued From P 1

In Oct 2023, GST Council had imposed 28% tax on full face value of online gaming bets.

Gaming industry, however, has been advocating for the tax to be calculated on gross gaming revenue (GGR) rather than face value of bets.

Online gaming companies had received show-cause notices alleging GST evasion of Rs 1.12 lakh crore. As GST Act allows the department to impose a penalty of up to 100% of tax demand, the total liability will add up to around Rs 2.5 lakh crore.

Examining the issue threadbare, bench said online gaming firms are not

mere facilitators but intermediaries but actionable claimant liable to pay responding to star the companies that erate skill-based bench said that based games character of be gambling for GST once money is stake certain outcomes.

The issue was lengthened in Karnataka Court, which passed order in favour of gaming companies. HC had said rummy was a game and that a company it was not supplying ble claims in the ma leged by tax department. The apex court, however, set aside HC's order.